

कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांक: एफ()FCA/उवसं/2023/
निमित्त,

दिनांक:

सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू-विज्ञान विभाग,
रूपवास (भरतपुर)

विषय:—Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in paharpur Block A & B for Mining and generation of employment and generation of District in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021) के संबंध में।

संदर्भ:—आपका पत्रांक 3237-38 दिनांक 20.12.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 12640 दिनांक 27.12.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 2 में आपने डायवर्टेड क्षेत्र में Safety Zone का डिमार्केशन किया जाने एवं बिन्दु संख्या 7 में डायवर्टेड क्षेत्र के बाउन्ड्री पिल्लर (आर.सी.सी. पिल्लर) स्थापित किये जाने के संबंध में अवगत करवाया गया है।

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा डायवर्टेड क्षेत्र में Safety Zone का डिमार्केशन एवं डायवर्टेड क्षेत्र के बाउन्ड्री पिल्लर (आर.सी.सी. पिल्लर) के सत्यापन हेतु आपको अपने संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दिनांक 28.12.2023 को मौके पर उपस्थित होने के लिए पाबंद करने हेतु लिखा गया था। लेकिन उक्त दिनांक को आपका कोई भी अधिकारी/कर्मचारी/प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण को आप द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रकरण में देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आपके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में इस कार्यालय अधीन क्षेत्रीय वन अधिकारी बयाना, वनखण्ड प्रभारी गौरव बंसल एवं सर्वेयर कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 28.12.2023 को मौके की वस्तुस्थिति निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि आप द्वारा लगाये जाने वाले कुल 158 आर.सी.सी. बाउन्ड्री पिल्लर (ब्लॉक ए में 75 एवं ब्लॉक बी में 83) में से केवल 8 पिल्लर ही लगाये गये हैं। एवं लगाये गये पिल्लरों पर अंकित किये जाने वाले क्रम सं० एवं जी.पी.एस. कोर्डिनेट्स भी गलत पाये गये हैं। साथ ही आप द्वारा किये जाने वाले लगभग 10-11 कि०मी० सेफटी जोन डिमार्केशन में से केवल 100-150 मी० सेफटी जोन का ही डिमार्केशन किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक दिनांक 517521/517521/2022 द्वारा 398.0085 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/MIN/125714/2021) में निम्नलिखित शर्तों के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की गयी थी। परन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि 1-1.5 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत होने के

RajKaj Ref

517521/517521/2022



कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

उपरान्त भी अभी तक आपके द्वारा विधिवत स्वीकृति में वर्णित शर्तों की पालना नहीं की गयी है, जिसकी वजह से वर्तमान 189.2515 है० वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/MIN/149012/2021) की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जा रही है। आप द्वारा बार-बार अपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है जिसकी वजह से प्रकरण में बेवजह देरी हो रही है।

अतः आपको पुनः अवगत करवाया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी विधिवत स्वीकृति दिनांक 11.03.2022 में निर्धारित समस्त शर्तों की पूर्ण पालना करवाकर रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवावें। ताकि प्रकरण में अनावश्यक देरी न हों।

(जी०के० वर्मा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांक: एफ() FCA/उवसं/2023/

दिनांक:

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. खनि अभियंता, भरतपुर।

उप वन संरक्षक
भरतपुर